



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 72] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 1991/माघ 18, 1912  
No. 72] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 1991/MAGHA 18, 1912

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

---

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बीमा प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1991

का.आ. 77(अ) :—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956  
(1956 का 31) की धारा 17(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनद् द्वारा

332GI/91

(1)

उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तत्काल प्रभाव से एक अधिकरण का गठन करनी है और निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है:—

- |   |         |
|---|---------|
| (1) श्री आर. एल. गुप्ता, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय                            | अध्यक्ष |
| (2) श्री आर. के. महाजन, भूतपूर्व बीमा नियंत्रक,<br>(सेवानिवृत्त)                    | सदस्य   |
| (3) डा. पी. वी. थामस, निदेशक,<br>भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,<br>ग्रामिक कार्य विभाग | सदस्य   |

2. इस अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[89(2)/इंश्यो-II/90]

एन. आर. रंगानाथन, विशेष सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 1991

S.O. 77 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 17(1) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby constitutes with immediate effect a Tribunal for the purpose of the said Act and appoints the following persons as members thereof, namely:—

- |  |          |
|--|----------|
| (1) Shri R. L. Gupta, Judge<br>of the Delhi High Court   | Chairman |
| (2) Shri R. K. Mahajan,<br>ex-Controller of Insurance<br>(Retired)   | Member   |
| (3) Dr. P. V. Thomas,<br>Director to the Govt. of India,<br>Ministry of Finance,<br>Department of Economic Affairs | Member   |

2. The headquarters of the Tribunal will be at New Delhi.

[89 (2)/Ins. II/90]

N. R. RANGANATHAN, Spl. Secy.